



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 161]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1985/चैत्र 8, 1907

No. 161]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1985/CHAITRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

का. आ. 277(अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./
85.—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का. आ. 613(अ)/
18चक/18कक/आई. डी. आ. ए./76, दिनांक 15
सितम्बर 1976 द्वारा इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरे-
शन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके
परन्तु प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैमर्स बंगाल पाटरीज
लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्व वाले 45 टगरा गड़, कल-
कत्ता और 3 पगलाडांगा रोड कलकत्ता स्थित औद्योगिक उप-
क्रमों के सम्पूर्ण प्रबंध को 15 सितम्बर, 1976 में पांच साल
की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 697(अ)/
18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./81 तारीख 14 सितम्बर,
1981 द्वारा, प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रमों

का एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रबंध करते रहने के
लिए प्राधिकृत किया था,

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 665
(अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 14
सितम्बर, 1982 का. आ. 174 (अ)/18चक/18कक/आई.
डी. आर. ए./83, तारीख 14 मार्च, 1983, का. आ. 660
(अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./83 दिनांक 14
सितम्बर, 1983 का. आ. 162 (अ)/18चक/18कक/आई.
डी. आर. ए./84 दिनांक 14 मार्च, 1984, का. आ. 479
(अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./84 दिनांक 30
जून 1984 तथा का. आ. 969/18चक/18कक/आई. डी.
आर. ए./84 दिनांक 28 दिसंबर, 1984 द्वारा प्राधिकृत
व्यक्ति को उक्त दो औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध 31 मार्च
1985 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए करते रहने के लिए
प्राधिकृत किया था ।

और केंद्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि सर्वसाधारण
के हित में यह समीचीन था कि प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्यो-
गिक उपक्रमों का प्रबंध करना जारी रखे, उद्योग (विकास
और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की

धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आदेश-द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय को दिया था जिसमें यह प्रार्थना की गई कि ऐसा प्रबंध तारीख 31 मई, 1985 तक की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ।

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 27 मार्च, 1985 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त दो औद्योगिक उप-क्रमों का प्रबंध तारीख 31 मई, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18-क के साथ पठित धारा 18-क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत को निर्देश देती है, कि वह 31 मई, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उप-क्रमों का प्रबंध करना जारी रखे ।

[फा. सं. 2(19)/75-सी.यू.एस.]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th March, 1985

S.O. 277|18FA|18AA|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 613(E)|18FA|18AA|IDRA|76, dated the 15th September, 1976 the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the two Industrial Undertakings at 45, Tangra Road, Calcutta, and at 3, Pagladanga Road, Calcutta, owned by Messrs Bengal Potteries Limited, Calcutta, for a period of five years from the 15th September, 1976.

And, whereas, by the order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 697(E)|18FA|

18AA|IDRA|81 dated the 14th September, 1981 the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period of one year.

And, whereas, by the orders of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 665(E)|18FA|18AA|IDRA|82 dated the 14-9-1982, S.O. 174(E)|18FA|18AA|IDRA|83 dated the 14th March, 1983, S.O. 660(E)|18FA|18AA|IDRA|83 dated the 14th September, 1983, S.O. 162(E)|18FA|18AA|IDRA|84 dated the 14th March, 1984, S.O. 479(E)|18FA|18AA|IDRA|84 dated the 30th June, 1984 and S.O. 969|18FA|18AA|IDRA|84 dated the 28th December, 1984, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto 31st March, 1985.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it was expedient in the interests of the general public that the authorised person should continue to manage the said Industrial Undertakings, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period upto and inclusive of 31st May, 1985.

And, whereas, the said High Court by its Order dated the 27th March, 1985 permitted the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto and inclusive of 31st May, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA read with section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto and inclusive of the 31st May, 1985.

[F. No. 2(19)/75-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.